ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.18, NO.1, JAN-JUNE,2023 /125

गरीबी उन्मूलन में मनरेगा का योगदान

* बाबूलाल गौतम एवं **डॉ0 रामसमुझ सिंह
* शोधार्थी–समाजशास्त्र एवं ** शोध पर्यवेक्षक
श्री लाल बहादुर शास्त्री पी0जी0 कालेज गोण्डा

आजादी के बाद भारत में काफी बड़े पैमाने पर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा काफी दिनों तक भारत गरीबी से जूझता रहा क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जनसंख्या के आधार पर ऐसा कोई आर्थिक सुधार के लिए कल, कारखाने, उद्योग केन्द्र, कृषी क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी ना थी, और शिक्षा, सामाजिकता, राजनीति आदि क्षेत्र विकास के क्षेत्र में जूझता रहा। भारत की गरीब जनता का जीवन बड़ी कठिनाइयों से जूझता रहा, कोई ऐसी ठोस व्यवस्था नही था कि यहां की गरीब जनता को स्थाई रूप में या गारन्टी के तौर पर रोजगार मुहैया करा सके। भारत के गरीब मजदूरों के लिए वही दैनिक मजदूरी पर जीवन कठिनाईयों के साथ जैसे–तैसे गुजारने के लिए मजबूर थे। भारत के कुछ बड़े–बड़े शहरों में कलकत्ता, मुम्बई, दिल्ली, गुजरात में छोटे–छोटे कल, कारखाने थे। ग्रामीण के मजदूरों को परिवार का भरण–पोषण के लिए गॉव शहर के लिए पलायन करना मजबूरी था। गांव के मजदूर शहर में जाकर कठिन परिश्रम करके थोड़ा बहुत पैसा कमा पाते थे जिससे सिर्फ परिवार का भरण–पोषण भी सम्भव न था काफी लम्बे समय तक ये सिलसिला भारत के गरीबों के लिए चलता रहा। धीरे–धीरे देश का विकास नये विचार नयी योजनाओं से बढ़ना शुरू हुआ लगभग आजादी के 60 वर्षो बाद गरीबों के लिए एक बेहतर योजना का निर्माण भारत सरकार द्वारा सन् 2005 में हुआ जिसका नाम नरेगा था। सन् 2006 में इस योजना का विस्तार कुछ प्रदेशों में संचालित किया गया। परिणाम अच्छे आने से सरकार एवं गरीबों का मनोबल बढ़ने लगा इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब वेरोजगारों को 100 दिन की मजदूरी गारण्टी के साथ उपलब्ध कराना, बाद में इस योजना का नाम परिवर्तन करके (मनरेगा) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना कर दिया गया, जो आज पूरे भारत में विधिवत रूप से संचालित है। इस समय लगभग 41.5 करोड लोग इस योजना के तहत रोजगार पा रहे है और उनके घरों में एक जीवन–जीने एवं बच्चों के भरण–पोषण की आस जग गयी है। लोगों को एक भरोसा जग गया कि मनरेगा के तहत 100 दिन की मजदूरी जरूर मिलेगा जिससे घर, परिवार चलाने में आसानी हुआ है।

गरीबी, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक, असमानता की वजह बनती रही, देश में गरीबी उन्मूलन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं एकीकृत बाल विकास परियोजना (आई.सी.डी.एस.) जैसी योजनाएं संचालित है। महात्मा गांधी राश्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना और एकल तथा सामूहिक उद्यम पर आधारित स्कीम से आजीविकाएं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना सृजित की जाती है।

सामाजिक, आर्थिक, जातीय, जनगणना (एस.इ.सी.सी.) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हितग्राहियों की पहचान जॉबकार्ड के प्रभावी वितरण के साथ हितग्राहियों को पीडीएस सिस्टम से जोड़ा

जा रहा है। इसी तरह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों में कौशल विकास कार्यक्रमों (स्किल डेवलपमेंट, प्रोग्राम) से रोजगार और उद्यमिता के जरिए आप का वैकल्पिक साधन मुहैया कराया जा रहा है। सिंचाई परियोजनाऐं बायो फर्टिलाइजर की मदद से कृषी उत्पादकता बढ़ाकर किसान आर्थिक सुरक्षा हासिल कर रहे है। ऐसे प्रयासों का नतीजा यह है कि देश में गरीबी का स्तर कम हुआ है। 17 अक्टूबर 2011 को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम (यू.एन.डी.पी.) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एण्ड ह्यूमन डेवेलेपमेंट इनिशिएटिव (ओ.पी.एच.आई.) द्वारा जारी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स कहता है कि भारत में 41.5 करोड़ लोग (2005–6 से 2019–21 के बीच) गरीबी से मुक्त हुए है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 की रिपोर्ट को माने तो भारत की जनसंख्या के 25.01 फीसदी लोगों की बहुआयामी गरीब के रूप में पहचान की गई है। ग्रामीण इलाकों में यह ऑकड़ा 32.75 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 8.81 फीसदी है।

इस योजना के तहत गांव के गरीबों को जो विल्कुल झुग्गी, झोपड़ी में किसी तरह से जिन्दगी काट रहे थे। ऐसे लोगों को आवास उपलब्ध कराकर उनकी जिन्दगी में खुशी दिलाने का काम किया। इस योजना के अन्तर्गत गांव में नाली, नाला, खड़न्जा, का निर्माण कराकर गांव की गरीब जनता को सुख, पूर्वक जीवन जीने का अवसर दिया है। इस योजना के द्वारा पशुचर, पशुसेड, का भी निर्माण सम्पूर्ण भारत में बड़े पैमाने पर कराने का कार्य किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) योजना के तहत गांव के लोगों को जब अधिक से अधिक महिलायों को रोजगार मिलने लगा तो महिलाएं अपने घर परिवार बच्चों के स्वास्थ पर, खान, पान पर विशेष ध्यान देने लगी जिससे लोग निरोग और स्वस्थ्य जिन्दगी जी रहे है। दिन–प्रतिदिन गॉव से तमाम ऐसी बीमारियॉ अब दूर होने लगी है। अब गांव के लोग भी अपना जीवन स्वास्थ पूर्वक जी रहे है। माता–पिता के अन्दर जागरूकता आने के कारण वे अपने बच्चों को समयानुकूल बनाने का प्रयास कर रहे है। शिक्षा, स्वास्थ, सामाजिकता की दायरा अब गांव का भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लोग पुरानी परम्पराओं से दूर हो रहे है। जैसे बाल विवाह, अशिक्षा, बेटियों को शिक्षा से दूर रखना, बालश्रम, आदि परम्परा की खात्मा गांव से होना शुरू हो चुका है।

निष्कर्ष :– पिछले कुछ वर्षो की भॉति वर्तमान में गरीबों की स्थितियों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उनके अन्दर सामाजिकता आ रही है। गरीबों के बच्चे अच्छी, शिक्षा, खाना, कपड़ा, का उपभोग कर पा रहे है। गरीब महिलाओं के अन्दर स्वाभिमान, सम्मान की भावना आ रही है। इन सबका मुख्य कारण वर्तमान में नये–नये तरीके से हो रहे आर्थिक क्षेत्रो में बृद्धि जिसमें कुछ हद तक (मनरेगा) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना का भी प्रमुख योगदान माना जाता है। जब भारत में मनरेगा नही था तब उस समय गरीब लोगों से मनमानी ढंग से काम कराना और बदले में बहुत कम मजदूरी देकर उसका शोषण करना ये काफी दिनों तक प्रकिया चलता रहा। जब मनरेगा योजना की शुरूआत देश में हुआ तो ग्रामीण मजदूरों में मजदूरी के प्रति एक जागृति आई कि मनरेगा से कम मजदूरी पर किसी का काम नही करना है। ग्रामीण मजदूरों को एक बल मिला जिसके श्रेय से उनकी अन्य दैनिक मजदूरी में भी बृद्धि आयी। इस योजना के अन्तर्गत तमाम गरीबो को आवास, पशुसेड, पानी निकासी की समुचित व्यवस्था, पेयजल आदि क्षेत्रों में विधिवत लाभ मिला है। महिलाओं बच्चों

के सामाजिक जीवन में बड़ी तीब्रता से परिवर्तन हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) से ग्रामीण गरीबों के गरीबी के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सन्दर्भ सूची :–

1–योजना जवनरी 2022 पृ0सं0–45
2–कुरूक्षेत्र अप्रैल 2023 पृ0सं0–15
3–मनरेगा सामाजिक, आर्थिक प्रभाव डॉ0 सीमा पारीक पृ0सं0–25
4–दैनिक समाचार पत्रों द्वारा।
5–पंचायती राज व्यवस्था पृ0सं0–33